कंवरजीत सिंह ढिल्लन

बनाम

हरदयाल सिंह ढिल्लन व अन्य

अक्टूबर 12, 2007

(तरूण चटर्जी और दलवीर भण्डारी, जे.जे.)

प्रोबेट का उत्तराधिकार अनुदान उसके बाद दावे की पोषणीयता - वसीयत के बल पर वसीयतकर्ता द्वारा छोडी गई सम्पत्तियों के संबंध में प्रोबेट दिया गया, यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया गया कि उक्त सम्पत्तियां संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी। विचारण न्यायालय (निचली अदालत) और उच्च न्यायालय ने प्रारम्भिक आपत्ति की अनुमति दी थी कि सक्षम द्वारा प्रोबेट के अनुदान के बाद प्रोबेट न्यायालय, मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं था।

प्रोबेट न्यायालय का कार्य यह देखना है कि वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत वास्तव में उसके द्वारा बिना किसी दवाब या अनुचित प्रभाव के एक उचित मानसिक स्थिति में निष्पादित की गई थी और उसे विधिवत प्रमाणित किया गया था। इसलिए, प्रोबेट न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है कि क्या वसीयतकर्ता के पास दावे की सम्पत्तियों को निपटाने का अधिकार था या नहीं, जिसे उसने अपनी

वसीयत द्वारा वसीयत किया था। प्रोबेट न्यायालय दावे की सम्पत्तियों के स्वामित्व के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए भी सक्षम नहीं हैं और न ही इस सवाल पर गौर करेगा कि क्या वसीयत द्वारा वसीयत की गई सम्पत्तियां संयुक्त पैतृक सम्पत्तियां थी या वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्तियां थी।

शीर्षक - वसीयतकर्ता के गुण, अधिकार और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए दावा। अपीलकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ साथ इस आरोप पर मुकदमा दायर किया गया है कि मुकदमें की सम्पत्तियां संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है। संयुक्त हिन्दू परिवार के मुकदमें में अपीलकर्ता द्वारा यह भी दावा किया गया कि पैतृक कृषि भूमि से आय का उपयोग करके, मुकदमें की सम्पत्तियों सहित विभिन्न सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया गया था- जैसे कि वादपत्र में लगाये गये आरोप हैं, जिन पर पक्षकारों को अनुमति देने के बाद ही मुकदमें पर निर्णय लिया जा सकता है। उनके संबंधित दावों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के बाद मुकदमें पर निर्णय लिया जा सकता है। उनके संबंधित दावों के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के बाद मुकदमें पर निर्णय लिया जावे, यह मानना मुश्किल है कि केवल इसलिए वसीयत का प्रोबेट दिया गया है।

शीर्षक और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा - उच्च न्यायालय के साथ कानून के फैसले में यह निर्देश दिए गये कि मुददों को तैयार करने के बाद मुकदमों का फैसला करना, जिसमें मुकदमें के सभी मुददे शामिल हैं।

विचारण न्यायालय को दावा पुनः तनकीयात कायम करने के पश्चात दावे की पोषणीयता व प्रोबेट देने के बारे में निर्देश देते हुए शीघ्र विचारण के निर्देश दिए।

चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह व अन्य, (1993) 2 एससीसी, 507 पर भरोसा किया।

श्रीमती रूकमणी देवी व अन्य बनाम नरेन्द्रलाल गुप्ता (1985) 1 एससीसी 144, अप्रयोज्य रखा गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय - सिविल अपील संख्या 4890/2007

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ के निर्णय व आदेश दिनांक 22.03.2004 से, जो कि सी.आर. सं. 3861/2002 में पारित किया गया।

अपीलार्थी की ओर से अनिल नौरिया और सुमिता हजारिका।

प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रदीप गुप्ता, के.के. मोहन, सुरेश भारती, गगनदीप सिंह, कंधारी, मिथलेश आर्य व लक्ष्मीबाई।

न्यायालय ने आदेश दिया।

आदेश

1. विलम्ब क्षमा किया गया।

2. अनुमति दी गई।

3. यह अपील सिविल रिवीजन नंबर 3861/2002 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित 22 मार्च, 2004 के फैसले और अंतिम आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान सिविल न्यायाधीश, जालंधर के दिनांकः 18 जनवरी, 2000 के आदेश ने अपीलकर्ता की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे को खारिज कर दिया, इसकी पुष्टि की गई।

4. मूल रूप से, मुकदमे की संपत्ति ईशर सिंह (अपीलकर्ता के दादा) के नाम पर थी, जिसे बाद में उनके दो बेटों, एस.हजारा सिंह और एस.कृपाल सिंह के नाम पर बदल दिया गया। स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह अपीलकर्ता के पिता थे। स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह अपने पीछे कुछ चल और अचल संपत्ति छोड़कर चले गए, जिसमें जलंधर में स्थित 48 कनाल 10 मरला कृषि भूमि, एक आवासीय मकान नंबर 148, सेक्टर 27 ए, चंडीगढ़ और 20,000/- रुपये की दो जमा राशि शामिल थी। .10,000/- क्रमशः [इसके बाद इसे "दावे की संपत्तियों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा] अपीलकर्ता के अनुसार, स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह द्वारा छोड़ी गई वाद संपत्तियाँ उनकी पैतृक संपत्ति थी। स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह की मृत्यु के आठ साल बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह द्वारा छोड़ी गई एक अपंजीकृत वसीयत को पेश किया और पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में उसके प्रोबेट के लिए आवेदन किया। स्वर्गीय एस.कृपाल सिंह द्वारा निष्पादित उक्त वसीयत के अनुसार, चल और अचल दोनों ही मुकदमे

की संपत्तियों को स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह ने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में वसीयत कर दी थी। केवल स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह की विधवा और उनकी अविवाहित बेटी के पक्ष में निवास का अधिकार दिया गया था। हालाँकि, उपरोक्त प्रोबेट कार्यवाही में, अपीलकर्ता द्वारा आपत्तियाँ दायर की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि उक्त वसीयत जाली और मनगढ़ंत थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 को प्रोबेट प्रदान किया गया था और उसके बाद, मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, जिसने स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में प्रोबेट देने के उच्च न्यायालय के आदेश की भी पुष्टि की। दिनांक 9 मार्च, 1995 को मुकदमे की संपत्तियों के संबंध में स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह की वसीयत का प्रोबेट दिए जाने के बाद, अपीलकर्ता ने घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता ने इस आशय की घोषणा की मांग की कि वाद की संपत्तियाँ संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियां थी।

5. अपीलकर्ता के कहने पर दायर मुकदमे में, प्रतिवादी नंबर 1 ने एक आवेदन दायर करके प्रारंभिक मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया था कि स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत की प्रोबेट दिए जाने के बाद, सिविल कोर्ट के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे को आगे बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र और तदनुसार मुकदमे को खारिज कर दिया जाना चाहिए। सिविल

न्यायालय द्वारा तय किया गया प्रारंभिक मुद्दा निम्नलिखित प्रभाव वाला है:-

"क्या इस न्यायालय के पास माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 1991 के आदेश के तहत दी गई प्रोबेट के मद्देनजर अधिकार क्षेत्र है, जिसकी पुष्टि दिनांक 1 दिसंबर, 1993 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच द्वारा की गई थी और इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकः 02.07.1994 को की गई थी।"

6. दिनांकः 18 जनवरी, 2000 के एक आदेश द्वारा, विद्वान सिविल न्यायाधीश, जालंधर ने इस निष्कर्ष पर मुकदमा खारिज कर दिया कि एक बार प्रोबेट एक सक्षम प्रोबेट अदालत द्वारा प्रदान किया गया था, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे में अपीलकर्ता ने ऐसा नहीं किया था। प्रोबेट कार्यवाही को चुनौती दी गई, सिविल कोर्ट के पास उपरोक्त आधार पर मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता और मुकदमा खारिज कर दिया गया।

7. व्यथित महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी और उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश की भी पुष्टि की थी जिसमें कहा गया था कि सक्षम प्रोबेट अदालत द्वारा प्रोबेट दिए जाने के बाद मुकदमा चलने योग्य नहीं था। वर्तमान विशेष अनुमति याचिका उच्च न्यायालय के

उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर की गई है जिसके संबंध में अनुमति पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

8. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के साथ-साथ सिविल न्यायालय ने उपरोक्त प्रारंभिक मुद्दे पर मुकदमे को खारिज करने में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया है, यह मानते हुए कि सक्षम न्यायालय द्वारा प्रोबेट प्रदान किए जाने के बाद सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई कि सिविल न्यायालय के पास मुकदमे को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

9. यह सत्य है कि स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत का प्रोबेट सक्षम प्रोबेट न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है जो मुकदमे की संपत्तियों से संबंधित है। लेकिन हमें वादी में लगाए गए आरोपों पर गौर करना होगा। वादी ने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिविल वाद इस आशय की घोषणा के लिए था कि मुकदमे की संपत्ति एचयूएफ की संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति थी, जिसमें अपीलकर्ता और उसके दो भाई हरदयाल सिंह ढिल्लन और हरबंस सिंह ढिल्लन, मां सुरजीत कौर और अविवाहित बेटी अमरजीत शामिल थे। कौर सदस्य थी। स्थायी निषेधाज्ञा के लिए आनुषांगिक राहत की भी मांग की गई थी ताकि प्रतिवादी नंबर 1 को किसी भी तरह से मुकदमे की संपत्तियों को हस्तांतरित करने से रोका जा सके। यह दावा करने के अलावा कि मुकदमे की संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, वादपत्र में यह भी कहा गया था कि स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह

उपरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता थे और उन्होंने अपनी पैतृक कृषि भूमि से आय का उपयोग करके मुकदमे की संपत्तियों सहित विभिन्न संपत्तियों का अधिग्रहण किया था।

10. इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिया। श्रीमती रूकमणी देवी और अन्य बनाम नरेंद्र लाल गुप्ता, [1985] 1 एससीसी 144 ने सिविल कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि एक सक्षम प्रोबेट कोर्ट द्वारा दी गई प्रोबेट स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह की वसीयत की वैधता के बारे में निर्णायक थी जब तक कि इसे रद्द नहीं किया गया था और नहीं प्रोबेट को रद्द करने के लिए की गई कार्यवाही को छोड़कर उक्त वसीयत पर महाभियोग चलाने के लिए साक्ष्य स्वीकार किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रोबेट कोर्ट का निर्णय रेम में एक निर्णय होगा जो न केवल प्रोबेट कार्यवाही के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाध्यकारी होगा। उपरोक्त निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय ने सिविल कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा था कि मुकदमे को इस तथ्य के मद्देनजर खारिज किया जाना चाहिए कि प्रोबेट कोर्ट ने स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में पहले ही प्रोबेट दे दिया था। हम उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में व्यक्त विचारों से सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं और न ही हम सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता द्वारा स्वामित्व और निषेधाज्ञा की घोषणा

के लिए मुकदमा अन्य बातों के साथ-साथ इन आरोपों पर दायर किया गया है कि मुकदमा संपत्ति एचयूएफ की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है जिसमें अपीलकर्ता और उसके दो भाई हरदयाल सिंह ढिल्लन और हरबंस सिंह ढिल्लन, मां सुरजीत कौर और अविवाहित बेटी अमरजीत कौर सदस्य हैं। मुकदमे में अपीलकर्ता द्वारा यह भी दावा किया गया है कि पैतृक कृषि भूमि से आय का उपयोग करके, वाद संपत्तियों सहित विभिन्न संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। वादपत्र में लगाए गए ऐसे आरोप हैं जिन पर केवल तभी निर्णय लिया जा सकता है जब पक्षों को अपने-अपने दावों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, इसे केवल इसलिए बनाए रखना मुश्किल है क्योंकि स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह की वसीयत का प्रोबेट प्रदान किया गया है। स्वामित्व और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा कानून में चलने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि प्रोबेट कोर्ट का कार्य यह देखना है कि वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत वास्तव में उसके द्वारा बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के एक स्वस्थ मन की स्थिति में निष्पादित की गई थी और उसे विधिवत सत्यापित किया गया था। इसलिए, प्रोबेट कोर्ट के लिए यह निर्धारित करना सक्षम नहीं था कि स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह के पास मुकदमा संपत्तियों का निपटान करने का अधिकार था या नहीं, जिसे उन्होंने अपनी वसीयत में वसीयत किया था। प्रोबेट कोर्ट मुकदमे की संपत्तियों के स्वामित्व के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए भी सक्षम नहीं है और न ही

यह इस सवाल पर जाएगा कि क्या वसीयत द्वारा वसीयत की गई मुकदमा संपत्तियां संयुक्त पैतृक संपत्ति थीं या वसीयतकर्ता की अर्जित संपत्ति थी।

11. चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह और अन्य, [1993] 2 एससीसी 507 में, इस न्यायालय ने उपरोक्त विचारों को कायम रखते हुए और इस न्यायालय के साथ-साथ भारत के अन्य उच्च न्यायालयों के पहले के निर्णयों का पालन करते हुए पैराग्राफ 15 में देखा। पृष्ठ 515 जो निम्नानुसार है:-

"ईश्वरदेव नारायण सिंह बनाम श्रीमती कामता देवी में इस न्यायालय ने माना कि प्रोबेट की अदालत केवल इस सवाल से चिंतित है कि क्या मृत व्यक्ति की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के रूप में सामने रखा गया दस्तावेज़ विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया था। कानून और क्या इस तरह के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता का दिमाग ठीक था। यह सवाल कि कोई विशेष वसीयत अच्छी है या बुरी, प्रोबेट कोर्ट के दायरे में नहीं है। इसलिए, प्रोबेट कार्यवाही में एकमात्र मुद्दा वास्तविकता से संबंधित है और वसीयत का उचित निष्पादन और अदालत स्वयं इसे निर्धारित करने और अपनी हिरासत में मूल वसीयत को विकृत करने के कर्तव्य के अधीन है। उत्तराधिकार अधिनियम एक स्व-निहित कोड है जहां तक प्रोबेट, अनुदान या प्रोबेट के इनकार के लिए आवेदन करने का सवाल है या प्रोबेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की गई। यह अधिनियम के प्रावधानों के प्रावरणी में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। प्रोबेट कार्यवाही प्रोबेट

कोर्ट द्वारा अधिनियम में निर्धारित तरीके से आयोजित की जाएगी और किसी अन्य तरीके से नहीं। संलग्न वसीयत की एक प्रति के साथ प्रोबेट का अनुदान निष्पादक की नियुक्ति और वसीयत के वैध निष्पादन के बारे में निर्णायक रूप से स्थापित करता है। इस प्रकार, यह वसीयत के तथ्य और निष्पादक के कानूनी चरित्र को स्थापित करने से अधिक कुछ नहीं करता है। प्रोबेट कोर्ट स्वामित्व या संपत्ति के अस्तित्व के किसी भी प्रश्न का निर्णय नहीं करता है।"

(जोर दिया गया)

यह स्थिति होने के नाते और वादपत्र में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ सिविल कोर्ट भी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि वसीयत की प्रोबेट देर से निष्पादित होने के बाद एस. कृपाल सिंह को अनुमति दे दी गई, उपरोक्त आरोप पर स्वामित्व और निषेधाज्ञा की घोषणा का मुकदमा कानून में चलने योग्य नहीं कहा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी यह मानते हुए कि मुकदमा चलने योग्य नहीं था, स्वर्गीय एस. कृपाल सिंह की वसीयत की प्रोबेट के मद्देनजर, इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था, जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, रुकमणी देवी (सुप्रा) के मामले में). हम उच्च न्यायालय से सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं कि यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी लागू हो सकता है। इस निर्णय को पढ़ने से

यह नहीं पता चलेगा कि सक्षम न्यायालय द्वारा प्रोबेट दिए जाने के बाद, स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा कानून में चलने योग्य नहीं कहा जा सकता है। इस न्यायालय ने उस फैसले में जो कहा वह यह है कि एक बार जब एक सक्षम अदालत द्वारा प्रोबेट प्रदान कर दिया जाता है, तो यह स्वयं वसीयत की वैधता के बारे में निर्णायक हो जाएगा, लेकिन, यह निर्णायक नहीं हो सकता है कि क्या प्रोबेट अदालत वसीयतकर्ता के स्वत्व का भी फैसला करेगी। मुकदमे की संपत्तियों का निर्णय, हमारे विचार में, केवल साक्ष्य के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यह सच है कि सक्षम प्रोबेट अदालत द्वारा दी गई वसीयत की प्रोबेट को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसे स्वत्व के लिए मुकदमे का फैसला करते समय सिविल कोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता है, लेकिन प्रोबेट का अनुदान स्वत्व और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए निर्णायक नहीं हो सकता है। वसीयतकर्ता के पास मुकदमे की संपत्तियों पर कोई स्वामित्व था या नहीं।

12. ऐसी स्थिति होने पर, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करने के बाद उपरोक्त एकमात्र आधार पर अपीलकर्ता के मुकदमे को खारिज करने में अवैध रूप से काम किया था। उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट के निर्णयों को रद्द किया जाता है। ऊपर बताई गई सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। ट्रायल कोर्ट को अब मुद्दों को तय करने के बाद मुकदमे का

फैसला करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रोबेट दिए जाने के बाद मुकदमे की पोषणीयता का मुद्दा भी शामिल है, अगर इस बीच पहले से ही तय नहीं किया गया है और इस न्यायालय के आदेश की प्रति पेश होने की तारीख से एक साल के भीतर इसका निपटान करना है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस आदेश की प्रति भेजी जावे।

13. इस फैसले से अलग होने से पहले हम एक और पहलू व्यक्त कर सकते हैं. जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, एक मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसे उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करने के बाद पुनरीक्षण में पुष्टि की थी जिसे हम पहले ही यहां नोट कर चुके हैं। एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या अन्य मुद्दों पर निर्णय किए बिना प्रारंभिक विवाद्यक उठाया जा सकता है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 के मद्देनजर मुकदमा खारिज किया जा सकता है। इस मामले में हमारे निर्णय को देखते हुए, हम इस पहलू पर ध्यान देना उचित नहीं समझते हैं जिसे भविष्य में विचार के लिए खुला रखा गया है।

14. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। अपील बिना हर्जे के स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार, द्वितीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।